राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 117

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 5 अक्टूबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सबसे तेज दो सौ टेस्ट विकेट लेने वाले बायें हाथ के गेंदबाज बने जडेजा

>> 14

सरोकार

अब घर बैठे भी हो जाएगी स्तन कैंसर की जांच

दुर्गापुर : नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर के छात्रों ने ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन डिवाइस तैयार की है, जिससे महिलाएं घर बैठे रक्त के नमूने से जांच कर सकेंगी। 200 रुपये कीमत वाली बायो सेंसर डिवाइस पलभर में बता देगी कि महिला के रक्त में एचईआर-2 एंटीजन की मात्रा कितनी है। (पेज-10)

जागरण विशेष

बस्तर के दशहरा में 'पधारेंगे' 600 देवी-देवता

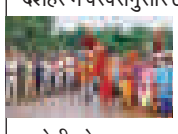

जगदलपुर : 75 दिन चलने वाले बस्तर के दशहरे में परंपरानुसार 600 देवी-देवताओं को आमंत्रित किया जाएगा। दंतेवाड़ा से सलामी देकर मां दंतेश्वरी के छत्र व डोली को बस्तर दशहरा के लिए रवाना किया जाता है। इस आयोजन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। (पेज-10)

रेपो रेट में एक और कटौती, सस्ता मिलेगा लोन

मौद्रिक नीति समीक्षा ▶ आरबीआइ ने रेपो रेट 25 आधार अंक घटाया, खपत और विकास दर को गति देना प्रमुख मकसद

आर्थिक माहौल को दुरुस्त करने की रिजर्व बैंक की एक और कोशिश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आर्थिक सुस्ती की चुनौती को दूर करने में जुटी केंद्र सरकार के साथ आरबीआइ भी कंधे से कंधा मिला कर खड़ा है। मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए आरबीआइ गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने रेपो रेट (जिस रेट पर केंद्रीय बैंक अल्पकालिक अवधि के लिए बैंकों को राशि उपलब्ध कराता है) में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे करीब दस वर्षों के न्यूनतम स्तर 5.15 फीसद पर ला दिया है। आरबीआइ गवर्नर दास ने पिछली पांच समीक्षाओं में पांच बार में रेपो रेट में कुल मिला कर 1.35 फीसद की कटौती की है। गवर्नर पद संभालने के बाद जितनी दफे उन्होंने मौद्रिक समीक्षा पेश की है उतनी दफे ब्याज दरों को घटाने का रास्ता साफ किया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक विकास दर के लक्ष्य को भी 6.9 फीसद से घटा कर 6.1 फीसद किया है।

शुक्रवार को रेपो रेट में कटौती का सीधा फायदा होम लोन या आटो लोन लेने वाले ग्राहकों को मिलना तय है, क्योंकि तकरीबन सारे बैंक अपनी कर्ज की दरों को रेपो रेट से लिंक कर चुके हैं। रेपो रेट की इतनी कम दर इसके पहले दिसंबर, 2010 में तब थी जब यह 5 फीसद के स्तर पर था। तब भी भयंकर वैश्विक मंदी की काट खोजने के लिए आरबीआइ की तरफ से ब्याज दरो में भारी कटौती की गई थी। लेकिन इस बार की कटौती का मकसद घरेलू मांग में वृद्धि करते हुए मंदी को दूर करना है। पिछली चार मौद्रिक नीति समीक्षाओं में रेपो रेट में 1.10 फीस की कटौती की गई थी, लेकिन उसका पूरा फायदा ग्राहकों को नहीं मिला। केंद्रीय बैंक ने भी इस पर नाराजगी भी जताई है। रेपो रेट घटाकर बैंकों को सस्ते कर्ज के लिए प्रोत्साहित करने के पीछे वजह भी यही है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाई जा सके। इससे त्योहारी सीजन में ऑटोमोबाइल, हाउसिंग, उपभोक्ता सामान सेक्टर पर सकारात्मक असर पड़ने के आसार हैं। वैसे भी कुछ दिन पहले ही सरकारी व निजी क्षेत्र के बैंकों ने देश भर में कर्ज आसानी से देने के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का एलान किया है। देश के 226 जिलों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने उपभोक्ता कर्ज वितरित करने के लिए खास अभियान शुरू किया है। इसके पहले आरबीआइ रेपो रेट कटौती का फायदा तत्काल ग्राहकों को देने के उद्देश्य से बैंकों की कर्ज की दर को रेपो रेट से लिंक करने का निर्देश जारी किया था। तकरीबन दर्जनभर बैंकों ने इसी महीने से इसे लागू भी कर दिया है।

मुंबई में आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बात की। प्रेट्र

समीक्षा की मुख्य बातें

- 25 आधार अंकों की कटौती के बाद रेपो रेट 5.15 फीसद पर आया
- त्योहारी सीजन में आटो, होम लोन की दरों में कटौती तय
- आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.9 से घटाकर 6.1 फीसद किया
- काबू में रहेगी महंगाई, अधिकतम 3.7 फीसद रहेगी महंगाई दर
- विदेशी मुद्रा भंडार 21.7 अरब डॉलर बढ़ कर 434.6 अरब डॉलर हुआ
- माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के लिए कर्ज की सीमा 1.25 लाख रुपये

घटाया विकास दर का अनुमान

नई दिल्ली : इकोनॉमी के समक्ष मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष (2019-20) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। रिजर्व बैंक का मानना है कि ताजा हालात में इस वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर सिर्फ 6.1 परसेंट रहेगी। अभी तक आरबीआइ को जीडीपी में 6.9 परसेंट वृद्धि दर की उम्मीद थी। हालांकि केंद्रीय बैंक ने माना है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही (अक्टूबर, 2019-मार्च, 2020) से आर्थिक विकास के मोर्चे पर सुधार दिखने शुरू हो जाएंगे। (पेज-12)

फैसले का चौतरफा स्वागत

वित्त मंत्रालय, बैंक और उद्योग जगत ने आरबीआइ के फैसले का स्वागत किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि हाल के दिनों में केंद्र की तरफ से विकास दर को तेज करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उसे केंद्रीय बैंक का फैसला और प्रभावशाली बनाएगा। केंद्रीय बैंक ने इस वर्ष 23 अगस्त के बाद से बैंक विलय, कारपोरेट टैक्स घटाने और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अलग फंड बनाने समेत कई कदम उठाए हैं। उधर, फिक्की, सीआइआइ, एसोचैम समेत तमाम उद्योग चैंबरों ने कहा है कि इससे निवेश का माहौल सुधारेगा। सीआइआइ के महासचिव चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, वर्ष भीतर ब्याज दरों में 135 आधार अंकों की कटौती से कारपोरेट सेक्टर उत्साहित है। फियो और ऑटोमोबाइल कंपनियों के संगठन सियाम ने भी कटौती को सकारात्मक बताया है।

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

एक को छोड़ हमारे सारे पड़ोसी अच्छे : एस.जयशंकर

नई दिल्ली : पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि बस एक को छोड़कर हमारे सारे पड़ोसी अच्छे हैं। साथ ही उन्होंने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआइ) परियोजना में भारत के शामिल होने की संभावना से साफ इन्कार कर दिया।

महासमर ▶ पृष्ठ 4

ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त होगी : निरूपम

मुंबई : मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके संजय निरूपम ने कहा है कि पार्टी में जिस तरह टिकट बांटे गए हैं, तीन- चार सीटों को छोड़ दिया जाए तो मुंबई की शेष सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। दिल्ली में बैठे लोग सच्चाई का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें जमीनी हकीकत का पता नहीं है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

बाढ़ पीड़ित बिहार को 613.75 करोड़ की केंद्रीय मदद

नई दिल्ली : पटना समेत बिहार के कई जिलों में आई बाढ़ से हुए नुकसान से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 613.75 करोड़ की अतिरिक्त मदद देने का फैसला किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार व कर्नाटक में बाढ़ से हुई क्षति के आकलन के बाद अतिरिक्त सहायता राशि जारी करने का आदेश दिया है। इसी तरह कर्नाटक को 1200 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि देने का निर्णय किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

पाक में गैर-मुसलमान नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति

इस्लामाबाद : भारत पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाने वाले पाकिस्तान ने खुद अपने मुल्क के अल्पसंख्यक समुदाय को एक प्रमुख अधिकार से वंचित कर दिया है। पाकिस्तान की संसद ने उस संविधान संशोधन विधेयक को बहुमत से खारिज कर दिया है, जिसमें गैर-मुसलमानों को भी देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाए जाने का प्रावधान था।

अगले सत्र से सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होगी एक परीक्षा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नवगठित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग कानून में है इसका प्रावधान
- हर्षवर्धन ने जताई उम्मीद, तय समय से पहले होगा आयोग का गठन

हर्षवर्धन फाइल फोटो

अगले शैक्षणिक सत्र से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और जिपमेर (जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च) समेत देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस में प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा होगी। इसके लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) का आयोजन किया जाएगा। अभी तक एम्स और जिपमेर में दाखिले के लिए अलग प्रवेश परीक्षा होती थी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को यह घोषणा की। उनके अनुसार, मानसून सत्र में पारित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का गठन तय समय से पहले करने की कोशिश की जा रही है और अगले सत्र यानी 2020-21 से वह देश में मेडिकल शिक्षा की निगरानी व नियमन की बागडोर संभाल लेगा। सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा का प्रावधान राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग कानून में था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि इसे कब से लागू किया जाएगा। जाहिर है कानून को लागू करने से पहले राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का गठन भी हो जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आयोग के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति और राज्य मेडिकल काउंसिल के सदस्यों के नाम भेजने को कहा गया है। अभी तक 23 कुलपति, 22 राज्य मेडिकल काउंसिल के सदस्य के नामांकन आ चुके हैं। इनमें से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के लिए नौ उपकुलपतियों व 10 राज्य मेडिकल काउंसिल के सदस्यों का चयन लॉटरी से किया जाएगा। 14 अक्टूबर को मीडिया के सामने पूरे पारदर्शी तरीके से लॉटरी निकाली जाएगी।

हर्षवर्धन ने कहा, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अध्यक्ष, चार स्वायत्त बोर्डों के सदस्य और सचिव के चयन की प्रक्रिया भी चल रही है। इसके लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली चयन समिति विभिन्न पदों के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करेगी।

एनएमसी में नहीं होगा केंद्र का दबदबा : हर्षवर्धन ने इन आशंकाओं को भी खारिज किया कि एनएमसी में केंद्र सरकार का दबदबा होगा। उन्होंने कहा, 33 सदस्यों वाले एनएमसी में 19 सदस्य राज्यों द्वारा नामित किए जाएंगे। इनमें राज्य के मेडिकल यूनिवर्सिटी के 10 कुलपति और राज्य मेडिकल काउंसिल के नौ सदस्य शामिल हैं। सदस्यों की नियुक्ति सिर्फ एक बार चार साल के लिए होगी। सदस्यों को नियुक्ति के समय और कार्यकाल पूरा होने पर दोनों बार अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी।

लेह और ऊधमपुर में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज

जम्मू : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दो और नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है। यह कॉलेज लेह और ऊधमपुर जिलों में स्थापित किए जाएंगे। कॉलेजों की स्थापना के लिए 325 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराना बहुत बड़ी चूक थी : वायुसेना प्रमुख

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- बालाकोट के बाद पाक के जवाबी हमले के समय वायुसेना ने एमआइ-17 पर दाग दी थी अपनी ही मिसाइल
- कोर्ट ऑफ इनक्वायरी में दोषी पाए गए दो अफसरों के खिलाफ हुई कार्रवाई

एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रेसवार्ता की। इस दौरान वह कुछ इस अंदाज में दिखे। जगदीश यादव

वायुसेना के नए एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने माना है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के जवाबी हमले के दिन (27 फरवरी) अपने ही एमआइ-17 हेलीकॉप्टर को मार गिराना बहुत बड़ी चूक थी। कोर्ट ऑफ इनक्वायरी में यह साबित हो गया है कि वायुसेना ने अपनी मिसाइल से गफलत में हेलीकॉप्टर को मार गिराया। दोषी पाए गए दो अफसरों पर कार्रवाई की गई है।

वायुसेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली प्रेस कांफ्रेंस में एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा, दो अफसरों पर एक्शन के अलावा जांच रिपोर्ट के आधार पर दूसरे कदम भी उठाए जा रहे हैं। ज्ञात हो, बालाकोट हमले के अगले दिन एमआइ-17 हेलीकॉप्टर बड़गाम में सीमा की निगरानी कर रहा था। इसी क्रम में भारतीय वायुसेना के स्पाइडर एयर डिफेंस ने हेलीकॉप्टर को दुश्मन का समझकर इसे मिसाइल से मार गिराया था। इसमें पायलट समेत छह वायुसेनाकर्मियों की मौत हो गई थी। कोर्ट ऑफ इनक्वायरी में पाई गई त्रुटियों में यह बात भी सामने आई है कि हेलीकॉप्टर में दोस्त या दुश्मन का संदेश देने वाला संचार तंत्र काम नहीं कर रहा था। इस बारे में पूछे जाने पर भदौरिया ने कहा, जो भी कमियां थीं उन्हें दुरुस्त कर लिया गया है। अब दुश्मन हमारे रेडियो संचार तंत्र को सुन नहीं सकते। बालाकोट को सफल एयर स्ट्राइक बताते हुए उन्होंने कहा, हमने पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया। अगले दिन पाकिस्तान के जवाबी एक्शन में हमने दुश्मन के एक एफ-16 विमान को मार गिराया और अपना एक मिग-21 विमान खोया।

भदौरिया ने कहा, बालाकोट हमले का असर नहीं हुआ होता तो सीमा पार से आतंकी गतिविधियों का स्तर कहीं ज्यादा होता। उन्होंने कहा, बेशक अभी भी पाक में काफी आतंकी कैंप हैं, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि हम सब पर हमला करेंगे। सरकार जब कहेगी तब कार्रवाई करेंगे। वायुसेना हर चुनौती के लिए तैयार है। गुलाम कश्मीर के लिए भी अलग से किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। पाक से ड्रोन के जरिये भारत में हथियार गिराने की घटनाओं से जुड़े सवाल पर वायुसेना प्रमुख ने कहा, यह सुरक्षा के लिए नए तरीके का खतरा है।

राफेल से मिलेगी ताकत, मई 2020 में भारत आएंगे पहले चार राफेल पेज>>5

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घटाया सुनवाई का एक दिन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- अब 18 के बजाय 17 अक्टूबर तक पूरी होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

अयोध्या राम जन्मभूमि पर मालिकाना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई का एक दिन घटाते हुए कहा कि अब सुनवाई 17 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी।

18 अक्टूबर तक सुनवाई का शेड्यूल तय कर चुकी अदालत ने यह बात तब कही जब रामलला के वकील सीएस वैद्यनाथन ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन की लंबी खिंचती दलीलों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोर्ट सुनवाई का शेड्यूल तय कर दे क्योंकि धवन ने अभी अपना पहला नोट भी खत्म नहीं किया है और इन्हें दो नोट और पढ़ने हैं। यह अपनी बहस कब पूरी करेंगे। इस पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि अगले सोमवार यानी 14 अक्टूबर को धवन मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस पूरी कर लेंगे। इसके बाद 15 और 16 अक्टूबर को हिंदू पक्ष जवाब खत्म कर लेगा। 17 अक्टूबर को कोर्ट वैकल्पिक मांगों पर पक्षकारों का पक्ष सुनेगा और शुक्रवार को छुट्टी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि 17 अक्टूबर तक बहस पूरी हो जाएगी। बहस की समयसीमा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधान न्यायाधीश 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उससे पहले मामले में फैसला आएगा। अगर 17 अक्टूबर को सुनवाई खत्म होती है तो अदालत के पास सिर्फ चार कार्यदिवस बचे हैं। (पेज-3 देखें)

पीएमसी बैंक के पूर्व सीएमडी गिरफ्तार

- ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज कर मुंबई और आसपास के छह स्थानों पर छापेमारी की
- कोर्ट ने राकेश, सारंग को नौ अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में सौंपा

मुंबई, प्रेट्र : पंजाब एवं महाराष्ट्र कोआपरेटिव (पीएमसी) बैंक जालसाजी मामले में बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थामस को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। ईओडब्ल्यू ने थामस को पूछताछ के लिए बुलाया था जहां पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ईओडब्ल्यू की एफआइआर के आधार पर पीएमसी बैंक जालसाजी मामले में मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद मुंबई एवं आसपास के छह स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 12 महंगी कारें जब्त की हैं।

वहीं, स्थानीय कोर्ट ने 'हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' (एचडीआइएल) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक राकेश वधावन और उसके बेटे सारंग को नौ अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में सौंप दिया है। गुरुवार को ईओडब्ल्यू ने दोनों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने उनकी 3500 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। दोनों की हिरासत की मांग करते हुए ईओडब्ल्यू ने कोर्ट को बताया कि पीएमसी बैंक ने एचडीआइएल समूह के 44 ऋण खातों की जगह 2100 से ज्यादा जाली ऋण खाते तैयार कर लिए और उसके बाद समूह ने अपना डिफाल्ट छिपाया था। एचडीआइएल के खातों की बकाया राशि 21,049 फर्जी खातों से ज्यादा थी। ये ऋण कोर बैंकिंग प्रणाली में दर्ज नहीं किए गए और इसकी जगह कर्ज खाते के ब्योरे में मामूली इंट्री की गई थी। बैंक के निदेशक मंडल और तत्कालीन प्रबंध निदेशक थामस को इस गतिविधि की पूरी जानकारी थी। जालसाजी में राकेश और सारंग ने मुख्य भूमिका निभाई थी इसलिए उनसे पूछताछ जरूरी है।

वहीं, ईडी सूत्रों ने बताया कि अतिरिक्त सबूत एकत्र करने के लिए छापे मारे गए हैं। ईडी और मुंबई पुलिस ने एचडीआइएल के प्रमोटरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक की शिकायत के आधार पर अधिकारियों के खिलाफ फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों के तहत इस सप्ताह की शुरुआत में पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार वर्ष 2008 के बाद से बैंक को 4,355.46 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

एफआइआर में पीएमसी बैंक के पूर्व चेयरमैन वरयम सिंह, प्रबंधक निदेशक जॉय थामस, एचडीआइएल के निदेशक राकेश वधावन को नामजद किया गया है। इसी एफआइआर को ईडी ने संज्ञान में लिया है। अनियमितता के बारे में पुलिस एफआइआर में कहा गया है कि एचडीआइएल प्रमोटरों ने बैंक प्रबंधन के साथ सांठगांठ कर उसकी भांडुप शाखा से कर्ज लिया था। ईडी सूत्रों ने कहा कि आरोपितों की दागी संपत्ति पर नजर डाली जा रही है ताकि उन्हें पीएमएलए के तहत अटैच किया जा सके।

हनी ट्रैप मामले में बार-बार क्यों बदला जा रहा है एसआइटी प्रमुख

नईदुनिया, इंदौर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि हनी ट्रैप मामले में गठित एसआइटी के प्रमुख को बार-बार बदला जा रहा है। अदालत ने सरकार को मामले की तमाम नोटशीट और दस्तावेज के साथ 21 अक्टूबर को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी तय किया कि भविष्य में इस मामले में दायर सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ होगी। (पेज-6)

छत्तीसगढ़ में 82 फीसद आरक्षण पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आरक्षण बढ़ाने के मामले में झटका दिया है। चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की पीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार के उस अध्यादेश पर स्थगनादेश दे दिया है, जिसमें सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसद कर दिया था। राज्य सरकार के इस कदम से केंद्र के गरीब सवर्णों को दस फीसद कोटे को मिलाकर राज्य में आरक्षण 82 फीसद हो गया था। (पेज-6)

अनोखा अहसास

चल पड़ी सफर में अनोखा अहसास कराने वाली देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन, उप्र के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, सुविधाएं और सत्कार देखकर यात्री बोले-वाह क्या बात है

तेजस के साथ रेलवे ने नए युग में रखा कदम

निशांत यादव, लखनऊ

नारंगी और काले रंग के विशेष परिधान में केबिन क्रू सदस्यों (ट्रेन होस्टेस) की मुस्कान...उन्ही के हाथों हर यात्री को तिलक लगा और फूलों की माला पहनाकर आतिथ्य सत्कार भी। यात्री सीट पर बैठे ही थे कि वेलकम ड्रिंक पेश किया गया। सीट के ऊपर लगा बटन दबाते ही 'ट्रेन होस्टेस' सेवा में हाजिर। यह दृश्य है देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन का जिसे शुक्रवार सुबह 9:55 बजे लखनऊ जंक्शन से उप्र के मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने रवाना किया। तेजस का पहला सफर करने वाले यात्रियों की एक्जीक्यूटिव क्लास में 48 और चेयरकार में 408 यात्री मौजूद थे। हर सीट पर टूरिस्ट मैगजीन थी। ट्रेन चलने के कुछ देर में ही सीट पर नारंगी रंग के नए कलेवर में रेल नीर की बोतल और गिलास दिया गया। पहली बार किसी ट्रेन में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल किया गया है। वाई-फाई ने बिना देरी यात्रियों को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। ट्रेन 11:04 बजे कानपुर पहुंची और शाम चार बजे नई दिल्ली। तेजस के पहले सफर को यादगार बनाने के लिए आइआरसीटीसी के एमडी एमपी मल ने हर यात्री को छाता और चाबी का गुच्छा भेंट किया। इस दौरान रेलवे बोर्ड चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि आने वाले समय में 50 कॉरपोरेट ट्रेनें चलेंगी।

ट्रेन में मना तेजस का बर्थडे : यह 'तेजस' का जन्म था और इसी ट्रेन के सात वर्षीय यात्री तेजस श्रीवास्तव का जन्मदिन भी। इस संयोग ने यात्रियों का मजा दोगुना कर दिया। रफ्तार के बीच बोगी में ही केक काटकर तेजस श्रीवास्तव का जन्मदिन मनाया गया।

संस्कृति की झलक दिखाएंगी बोगियां : इस ट्रेन की पांच बोगियों पर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की जानकारी होगी। हर बोगी की थीम अलग होगी। अवध थीम में जहां लखनऊ के टूरिस्ट स्थलों की झलक दिखेगी। वहीं साकेत थीम वाली बोगी में अयोध्या की दीपावली आरती, काशी थीम वाले कोच में बैठे लोग वाराणसी की संस्कृति को जान सकेंगे।

तेजस ने शुक्रवार को लखनऊ स्टेशन छोड़ने के साथ ही रेलवे को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। विमान जैसी सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में परिचारिकाओं ने यात्रियों का स्वागत किया। रेलवे की व्यवस्था से मुसाफिर बेहद संतुष्ट नजर आए। (प्रेट्र)

आगरा से वाराणसी के बीच सेमी हाईस्पीड ट्रेन चलाने के लिए भी हम तैयार हैं। प्रस्ताव आते ही हमारी सरकार जमीन मुहैया कराएगी।

- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

सुहाना सफर

ट्रेन होस्टेस करेंगी आवभगत, यात्रियों का 25 लाख रुपये का बीमा, सफर के दौरान घर में चोरी हुई तो एक लाख का बीमा

इस तरह तय होगा किराया : तेजस में डायनमिक किराया होगा, जो सीट की बुकिंग के हिसाब से घटेगा-बढ़ेगा।

लखनऊ - नई दिल्ली न्यूनतम किराया : चेयरकार : 1125 रुपये (185 रु. कैटरिंग चार्ज सहित), **एक्जीक्यूटिव क्लास :** 2310 रुपये

नई दिल्ली - लखनऊ : चेयरकार : 1280 रुपये (340 रु. कैटरिंग चार्ज), **एक्जीक्यूटिव क्लास :** 2450 रुपये

यह होंगे नियम

- रिफंड टीडीआर से नहीं, भुगतान आइआरसीटीसी सीधे करेगा
- डायनामिक फेयर व्यस्त, त्योहार, लीन सीजन के आधार पर
- फरवरी, मार्च और अगस्त लीन सीजन, किराया कम होगा

तेजस इसलिए कॉरपोरेट : ट्रेन का ऑपरेशन ही रेलवे (ड्राइवर और गार्ड) के पास रहेगा। टिकटिंग, पार्सल व अन्य व्यावसायिक कामकाज व यात्री सुविधाओं का जिम्मा आइआरसीटीसी का होगा। आइआरसीटीसी हर साल रेलवे को बोगियों के एवज में हॉलेज शुल्क देगा। (पेज-6 भी देखें)

रविदास मंदिर के लिए मिलकर तय करें वैकल्पिक जगह : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के तुगलकाबाद वन क्षेत्र में गुरु रविदास के मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे संबंधित पक्षकारों से मंदिर के लिए मिलकर बेहतर वैकल्पिक जगह तय करने को कहा है।

जस्टिस अरुण मिश्रा और एस. रवींद्र भट्ट की पीठ ने कहा, वह सभी की भावनाओं का सम्मान करती है लेकिन कानून का पालन तो करना ही होगा। पीठ ने प्रकरण से जुड़े पक्षकारों को वैकल्पिक स्थान के बारे में सर्वमान्य समाधान खोजने का निर्देश देते हुए इस मामले को 18 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

पीठ ने कहा, अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल भी इस मामले में पेश हो रहे हैं और सभी पक्षकारों को बेहतर स्थान के बारे में सर्वमान्य समाधान खोजने के लिए विचार-विमर्श करना चाहिए ताकि वहां पर मंदिर का निर्माण हो सके। इससे पहले, कोर्ट ने सवाल किया था कि उसके आदेश पर हटाए गए मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए संविधान के अनुच्छद 32 के तहत दायर याचिका पर कैसे विचार किया जा सकता है? यह याचिका दो पूर्व सांसदों-अशोक तंवर और प्रदीप जैन आदित्य- ने 27 अगस्त को दायर की थी। याचिका में उन्होंने अपने पूजा के अधिकार को लागू करने की अनुमति मांगी है। उनका आरोप है कि तुगलकाबाद में मंदिर और समाधि हटाए जाने के कारण उन्हें इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है। याचिका में कहा गया था कि आस-पास के क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के मामले में शीर्ष कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनेक तथ्य छुपाए गए थे। इसके साथ ही पूर्व सांसदों ने मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति मांगते हुए कहा था कि वह एक पवित्र स्थान है और वहां 500-600 वर्षों से पूजा अर्चना हो रही थी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शीर्ष कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर को हटाया था। कोर्ट ने नौ अगस्त को टिप्पणी की थी कि गुरु रविदास जयंती समारोह समिति ने पूर्व के आदेश के अनुरूप वन क्षेत्र खाली नहीं करके गंभीर उल्लंघन किया गया है। मंदिर हटाए जाने के बाद दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में गुरु रविदास के अनुयायियों ने कई स्थानों पर प्रदर्शन किए थे।